

होता है और बाहर विदेशों में भी होता है। इसलिए सुविधाओं का ज्ञान उन्हें नहीं था यह बात तो ठीक नहीं है।

**श्री नवल किशोर सिंह :** यह जो रेनवे ने इन से राय मांगी और इन्होंने राय दे दी इसके पूर्व इन्होंने टूरिस्ट एजेंसों जैसे संगठनों से पूछ लिया था या नहीं कि रेनवे को क्या राय दी जाय ?

**डा० सरोजिनो महिषी :** यह सारा बातें पूछ ली गई थी और टूरिज्म डेवलपमेंट कौमिल में भी इस की सारी चर्चा हो गई थी। बाद में इस में चूक फयदा नहीं हो रहा है इसे देखने के बाद ही रेनवे मन्त्रालय ने जब पूछा तब इसमें सहमति दी गई।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** अध्यक्ष महोदय, बड़ी सख्या में विदेशों में हिप्पी लोंग भारत में आ रहे हैं। क्या पर्यटन मन्त्रालय ने इस बात पर भी विचार किया है कि उन्हें कुछ और सुविधाएं दी जाय जिसमें उनकी सख्या बढ़े या सरकार ने यह मनाह दी है कि उनकी संख्या कम करनी चाहिए।

**डा० सरोजिनो महिषी :** सुविधाओं की सख्या काफी बढ़ रही है। लेकिन नाम मात्र सुविधाएं देने से अगर फायदा विदेशी मुद्रा में हमें नहीं बढना है और पर्यटकों को भी नहीं पहुंचता है तो वैसी सुविधाओं को काट दिया गया है। नहीं तो सुविधाओं को बढ़ाने के बारे में कोशिश की गई है। होटलों में एकमोडेशन की बात है या देश के अन्दर सरकार की बात है, एयर पोर्ट के सुधार की बात है, इन सब बातों में काफी सुविधाएं दी गई हैं और काफी प्रचार किया गया है।

#### Aid Agreement with Japan

\*283. SHRI R. KADANAPALLI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether any agreement was signed

between India and Japan for the Yen Credit to India for the purchase of non-project commodities and chemicals ; and

(b) if so, the main features thereof ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN) : (a) Yes, Sir.

(b) A Loan Agreement for Rs. 19 04 crores (\$25 39 million) was signed with the Export Import Bank of Japan and certain other Japanese banks on the 20th April, 1971 for financing imports from Japan of commodities, raw materials, intermediates, components, spare parts, steel rolls, etc., as also machinery for the National Small Industries Corporation.

The loan is repayable in 20 years, including a grace period of 7 years and carries interest at 5% per annum.

#### Ceiling on Urban Income

\*284. SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to impose ceiling on urban income in line with the legislation regarding ceilings on agricultural lands ; and

(b) what is the level of highest urban income and what is the percentage of population in that category ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN) : (a) While no formal ceiling is proposed, the combined incidence of changes introduced in the rates of personal income tax and wealth tax in the 1970-71 budget, together with the proposals for further modification of these rates in the budget for 1971-72, puts a virtual ceiling on urban incomes.

(b) Precise information is not available, but according to the latest available data on income tax statistics, which relates to 1966-67, there were only 207 individual assesseees in the annual income bracket of Rs. 5 lakhs and above in the financial year 1966-67 and their annual average pre-tax income worked out to Rs. 9.9 lakhs.